The Pioneer (Lucknow) 8 June, 2017

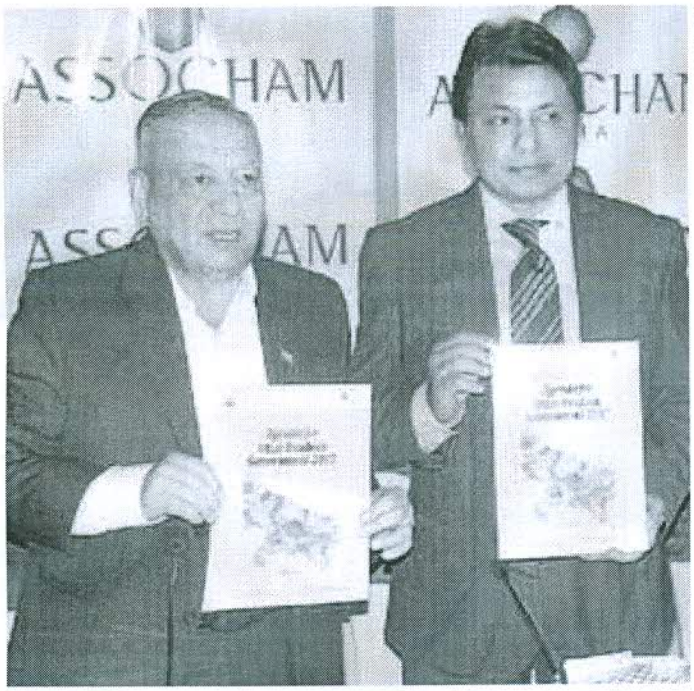

ASSOCHAM members meet CM, present agenda of growth

Lucknow (PNS): Members of ASSOCHAM met Chief Minister Yogi Adityanath on Wednesday to present to him the agenda of growth for Uttar Pradesh.

Secretary general DS Rawat, while talking to *The Pioneer*, said that in the agenda, they had suggested to the CM to promote small units which generated more employment in comparison to the larger ones. "We have also suggested that there should be value addition to agriculture because farmers were crucial to the development of the state," he said.

He said that the Chief Minister had asked them to draft an industrial policy in terms of what the industry wanted. "We will be creating a core group of people who are from the industries, both medium and large ones, as well as the senior bureaucrats to make a policy which was on par with the other states and will bring in a lot of investment," he said. He further pointed out that they were also shortly going to submit an agricultural policy to help in the doubling of the farmers' income.

The Times of India (Lucknow) 8 June, 2017

UP has highest migration rate in country: ASSOCHAM

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: A study conducted by the apex industry body, ASSOCHAM, claims that Uttar Pradesh has the highest migration rate in the country. To check this, it has suggested to the state government to focus more on creation of jobs through medium, small and micro industries and setting up skill centres to train modern workforce.

The members of Associated Chambers of Commerce of India (ASSOCHAM) also submitted a six-point development agenda for UP to chief minister Aditya Nath Yogi on Wednesday.

The study states that UP's net migration is more than the double of Bihar — the state next to UP in pan-India migration list.

It also states that migration of people (in the 20-29 age-group) jumped from 29,55,000 in 1991-2001 decade to 58,34,000 in 2001-11 decade.

The reasons for this were poverty and unemployment. As per Census 2011, UP is the most populous state in India and also home to the maximum number of poor — 22% of total poor in India.

ASSOCHAM president Sandeep Jajodia said, "UP has about 12 million youth who can contribute towards modern workforce. All we need is to set skill centres to train them in various crafts and skills. We have suggested to the CM to introduce district specific policies that would impart training and create jobs specific to that district."

The study also points out low telephone density in UP, which is 71.5% as compared to the national average of 90%. In Delhi, it is 238%. ASSOCHAM said this gap is also a major deterrent in the state's development.

ASSOCHAM will organise a Women Stand-Up Conclave in Lucknow in July to inculcate entrepreneurship skills among women and encourage them to begin start-ups. It has also suggested to the government to improve road infrastructure through maximum utilisation of Central funds like other states- MP, Andhra Pradesh, Gujarat etc.

Jajodia said, "The Centre has allocated Rs 4 lakh crore for infrastructure development in UP. It will help in the development of industries and drawing foreign direct investment in Uttar Pradesh to create employment opportunities."

ASSOCHAM'S SUGGESTIONS TO UP GOVT

Train farmers to adopt modern & scientific methods of agriculture

- Expedite integrated industrial township projects in Auraiya and Jhansi
- Creation of ₹100cr corpus to promote incubators and start-ups
- Introduce district specific skill & livelihood generation policies
- Revisit Energy policy 2009 to encourage pvt sector for capacity addition
- Provide broadband services in rural & distant areas via cable TV network

Creation of ₹100cr corpus to promote incubator and start-ups

Improve marketing linkages, financial access

Hindustan Times (Lucknow) 8 June, 2017

Assocham releases six-point development agenda for state

HT Correspondent
lkoreportersdesk@hindustantimes.com

LUCKNOW: Industry body Assocham has submitted a six-point five-year development agenda to chief minister Yogi Adityanath which may serve as a guide for the new government on areas that require attention.

The 'Action Agenda', jointly prepared by Assocham and Thought Arbitrage Research Institute (TARI), was released at a press conference here on Wednesday by Assocham president Sandeep Jajodia, Assocham secretary general DS Rawat and director, TARI, Kshama V Kaushik.

The study has recommended measures for making Uttar Pradesh a vibrant economy with focus on skill development, agriculture, horticulture, handicraft, handloom, leather and leather products.

Suggesting an economic road map for the government, the study says the net migration of people in the age group of 20-29 years was 58,34,000 in 2001-11, up from 29,55,000 in 1991-2001.

The paper adds that monitoring and management centres of the State Skill Development Mission should be set up at district level and focus of skilling programme should be on high growth areas such as agriculture, building and constructions, handloom and handicraft, food processing, healthcare, leather and unorganised sector.

District-specific policies for skilling and livelihood generation in migration-hit regions should be formulated, it adds.

The paper says economic growth of UP is critical for India since it is the most populous state as well as home to the most number of poor – 17% of the total population and 22% of the total poor (Census 2011).

The state's economic growth (GSDP) has been, for most of the time in the past decade, lower than the national average.

"The state's industrial sector is driven by the small and medium scale industries – contributing about 60% of total manufacturing output and significant employment (about 60 lakhs)," the document says.

ASSOCHAM IN THE NEWS

Pioneer – Hindi (Lucknow) **8 June, 2017**

एसोचैम ने योगी को दिया छह सूत्रीय नवोन्मेषी विकास एजेंडा

उप्र में पलायन रोकने के लिए क्षमता विकास व रोजगारपरक नीतियां बनानी होंगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

देश के शीर्ष उद्योग मंडल एसोचैम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए छह सूत्रीय नवोन्मेषी पंचवर्षीय विकास एजेण्डा पेश किया है। यह एजेण्डा प्रदेश की नई सरकार को उन क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा, जिनसे राज्य के विकास में तीव्रता लायी जा सकती है। द असोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम) और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (टारी) ने योगी सरकार के लिए एक सुझावरूपी एजेंडा 'एक्शन प्लान फॉर द न्यू गवर्नमेंट' तैयार किया है।

एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोदिया, महासचिव डीएस रावत तथा टारी की निदेशक क्षमा वी. कौशिक ने एक पत्रकार वार्ता में इस सुझाव पत्र को संयुक्त रूप से जारी किया। इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश को एक प्रखर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए जरूरी विभिन्न कदमों को लेकर सुझाव दिए गए हैं। इसमें क्षमता विकास, कृषि, औद्यानिकी, हस्तशिल्प, हथकरघा, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद क्षेत्रों पर खास जोर दिया गया है।

अगले पांच साल का आर्थिक रोडमैप प्रस्तुत करते हुए इस अध्ययन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और हाल के दशकों में यह सिलसिला और तेज हुआ है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच 20 से 29 साल आयु वर्ग के 58 लाख 34 हजार लोगों ने रोजगार के लिये दूसरे स्थानों पर पलायन किया, जबकि 1991 से 2001 के बीच यह आंकड़ा 29 लाख 55 हजार था। इस तरह से पलायन का आंकड़ा लगभग दोगुना हो चुका है।

एसोचैम के महासचिव रावत ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम खासकर उन कार्यों पर केन्द्रित होना चाहिए जिनसे श्रमिकों को अपने राज्य के बाहर काम मिलता है। इनमें निर्माण, संगठित खुदरा व्यवसाय एवं परिवहन (वाहन चालक) शामिल है। इससे उन्हें प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ मिलने में मदद मिलेगी। एसोचैम के अध्यक्ष जजोदिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास भारत की तरक्की के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ-साथ गरीबों की सबसे ज्यादा संख्या वाला प्रदेश भी है। यहां देश की कुल आबादी के 17 प्रतिशत लोग और जनगणना 2011 के हिसाब से गरीबों की कुल संख्या के 22 प्रतिशत निर्धन लोग निवास करते हैं।

अत्यन्त सम्भावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश अगर आर्थिक रूप से सशक्त भी हो तो वह पूरे देश के विकास का इंजन साबित हो सकता है। टारी की निदेशक क्षमा वी. कौशिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य बना हुआ. है लेकिन कम उत्पादकता तथा ज्यादा आबादी की वजह से फसल का बहुत कम ही आधिक्य उपलब्ध रह पाता है। विपणन में राज्य सरकार के सहयोग की कमी और सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों की उपज की कम खरीद होने की वजह से किसानों को आधिक्य रूपी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले काफी कम दाम पर बेचना पड़ता है। प्रदेश की नयी सरकार को इस चुनौती से निपटने के लिये नयी सोच के साथ काम करना होगा।

Navbharat Times (Lucknow) 8 June, 2017

10 साल में दोगुना हुआ युवाओं का पलायन

ऐसोचैम के सर्वे में खुलासा, सीएम को दिए सुझाव

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ

यूपी में नौकरी न मिलने की वजह से युवाओं का पलायन सबसे ज्यादा Q है। हाल यह है कि देश में सबसे ज्यादा यूपी से युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य जाते हैं। बीते 10 साल में यह संख्या दोगुनी हुई है। यह तथ्य सामने आया है एसोचैम के सर्वे में।

एसोचैम ने यह पलायन रोकने के लिए योगी सरकार को सुझाव भी दिए हैं। इसी सिलसिले में एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोडिया, महासचिव डीएस रावत और टारी की डायरेक्टर क्षमा वी कौशिक ने बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान सीएम को सुझाव पत्र भी दिया गया।

एसोचैम करेगा स्टैंडअप कॉन्फ्रेंस

एसोचैम के अध्यक्ष संदीप जजोडिया ने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में लखनऊ में महिला उद्यमियों क ी स्टैंडअप कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पर सहमति दी है। एसोचैम ने प्रदेश की नई उद्योग नीति में सरकार के साथ सहयोग करने की भी इच्छा जताई है। इसके लिए हम जल्द एक समिति का गठन करेंगे। यह समिति 15 जुलाई तक राज्य सरकार को अपने सुझाव सौंप देगी।

10 साल में 58.34 लाख युवा गए

रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच 20-29 साल के 58 लाख 34 हजार युवाओं ने पलायन किया है। जबकि 1991 से 2001 के बीच 29 लाख 55 हजार युवा प्रदेश से गए।

ऐसे रुकेगी यूथ पावर

यूपी से युवाओं का पलायन रोकने के लिए एसोचैम और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टिट्यूट (टारी) ने ये सुझाव दिए हैं।

- पलायन प्रभावित क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जिला आधारित नीतियां बनें।
- पूर्वांचल से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, ऐसे में यहां बड़े पैमाने पर कौशल विकास केन्द्र बनें।
- स्टार्टअप नीति पर ध्यान दिया जाए।
- औरैया और झांसी में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विकास, दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र की स्थापना,आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर आईटी निवेश क्षेत्र बने।

पलायन रोकने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम उन सेक्टर्स पर हों, जिनमें श्रमिकों को राज्य के बाहर काम मिल रहा है। इनमें मेन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट (ड्राइवर) शामिल हैं।-डीएस रावत, महासचिव, एसोचैम